

बिहार में चुनावी पारा गरम, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी मैदान में उतरे

धारा 370 व कृषि बिलों के फैसलों पर देश पीछे नहीं हटेगा: पीएम मोदी

राहुल का प्रधानमंत्री से सवाल: चीनी सैनिकों को हिन्दुस्तान की जमीन से कब भगाया जायेगा

(विशेष संवाददाता) रोहतास /भागलपुर, 23 अक्टूबर। बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और कृषि संबंधी तीन नये कानूनों पर कांग्रेस सहित विपक्ष के रूख की कड़ी आलोचना की और कहा कि देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। मोदी ने आरोप लगाया कि विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों से लगातार झूठ बोलने में जुट गए हैं और आज कल ये लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ही एमएसपी बढ़ाने की कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ने रोहतास, गया भागलपुर में चुनावी



रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, देश जहाँ संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के निशाना साधते हुए उन्हीं को बहना, मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सौधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था, तब इन्होंने कैसा भ्रम फैलाया था। कांग्रेस पर परोक्ष प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह राजग की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की और सरकारी खरीद केंद्र बनाने और

सरकारी खरीद, दोनों पर बहुत जोर दिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब ये लोग सरकार में थे, उसकी तुलना में बिहार में ही धान की सरकारी खरीद चार गुना और गेहूँ की सरकारी खरीद पांच गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा, जबजब, बिचौलियों और दलालों पर चोट की जाती है, तबतब ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का इंतजार देश भरसे कर रहा था या नहीं?

(विशेष संवाददाता) नवादा (बिहार), 23 अक्टूबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को सवाल किया कि हिन्दुस्तान की जमीन से चीनी सैनिकों को कब भगाया जायेगा। साथ ही कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि किसी चीनी सैनिक के हिन्दुस्तान की जमीन पर मौजूद होने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने बिहार के नवादा और कहलगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, हाल ही में बनाए गए कृषि संबंधी तीन कानून, जीएसटी, लोकडउन के



दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन और नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में

का मुद्दा भी उठाया। इस मुद्दे पर केंद्र और बिहार की राजग सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना वायरस संकट के समय लोगों की आर्थिक मदद नहीं कर किसानों, छोटे कारोबारियों, मजदूरों, छोटे उद्यमियों की कम्मर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही लोगों से खड़ा करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के साथ नवादा की रैली को संबोधित कर रहे राहुल ने बिहार में बेरोजगारी

जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके सामने वह अपना सिर झुकाते हैं..... पूरा देश बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि वे चीन को भारत की शक्ति दिखाने जा रहे हैं। चीन ने हिन्दुस्तान की 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले रखी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करते हुए आरोप लगाया, चीन की सीमा हिन्दुस्तान की सीमा के अंदर है। सवाल ये है कि जब चीनी सैनिक हमारी जमीन के अंदर आए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिन्दुस्तान के अंदर कोई नहीं आया?'

पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली। पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी (पोटैबल वाटर) की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगहजगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। सीजीडब्ल्यू के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। सीजीडब्ल्यू ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 08 अक्टूबर, 2020 को



पुकारा जाता है, वो यह सुनिश्चित करेगी कि भूजल से हासिल होने वाले पोटैबल वाटर यानी पीने योग्य पानी की बर्बादी और उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है।

2318 कैदियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश, अब छूट नहीं

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। कोरोना महामारी के मद्देनजर कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत/पैरोल की अवधि अब और नहीं बढ़ाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने 25 मार्च 2020 के अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत कोरोना महामारी के चलते अंतरिम जमानत और पैरोल की अवधि समयसमय पर बढ़ाई गई थी। न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर चल रहे गंभीर अपराधों में आरोपी 2318 विचाराधीन कैदियों को 2 नवंबर से 13 नवंबर के बीच संबंधित जिला अदालतों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। ये सभी जिला अदालतों से अंतरिम जमानत पाकर फिलहाल जेल से बाहर हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल, सिद्धार्थ मुद्गल और तलवर्त सिंह की विशेष पीठ ने कहा कि उसके 25 मार्च के आदेश के आधार पर इन विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन कैदियों को संबंधित अदालत में

कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी की गयी

(विशेष संवाददाता) नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर। भारत के पहले विश्व कप विजेता क्रिकेटर कप्तान कपिल देव की दिल का दौरा पड़ने के बाद शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी की गयी और अगले दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुड़ी मिलने की उम्मीद है। इस महान क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर बयान में लिखा, वह उबरने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली के सुंदर नगर में रहने वाले कपिल (61 वर्ष) को गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद यहां ओखला के फोर्टिस एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के आपात विभाग में ले जाया गया। अस्पताल ने अपने शुरुआती बयान में सिर्फ सीने में दर्द का ही जिक्र किया था, लेकिन फिर ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा, कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी जांच की गयी और रत में ही आपात कोरोनारी एंजियोप्लास्टी की गयी। इसके अनुसार, इस समय वह डा. अतुल माथुर और उनकी टीम की देखरेख में आईसीयू में हैं। उनकी हालत स्थिर है। उन्हें दो दिन में अस्पताल से छुड़ी मिलने की उम्मीद है। एंजियोप्लास्टी ब्लाॉक हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है ताकि हृदय में सामान्य रक्त संचार हो सके। बाद में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने वालों और उनके परिवार के प्रति समर्थन जताने वालों



स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूँ। कोहली ने ट्वीट किया, आपकें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहा हूँ। जल्दी ठीक हो जाइये पाजी। भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट किया, कपिल देव सर आपके जल्दी से ठीक होने की कामना करता हूँ। हमेशा मजबूत रहिये।

नौसेना ने अपनी तैयारियों का किया प्रदर्शन

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। भारत के रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में नौसेना ने युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए एक पोतरोधी मिसाइल से एक जहाज को नष्ट कर दिया। अरब सागर में किए गए इस अभ्यास में मिसाइल का निशाना 'बेहद सटीक' था। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो शुक्रवार को जारी किया। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और कई युद्धपोतों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, विमानों और नौसेना के अन्य उपकरणों को शामिल करने वाले एक व्यापक नौसेना अभ्यास के दौरान इस मिसाइल को 'फ्लटलाइन

पुलिस थाने में महिलाओं के लिए बनेंगे सीक्रेट रूम

(विशेष संवाददाता) लखनऊ, 23 अक्टूबर। मिशन शक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हर थाने में एक सीक्रेट रूम बनवाने के निर्देश दिए जो पूरी तरह से पारदर्शी व सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। इसमें पीड़ित महिला, महिला पुलिस कर्मी से बिना संकोच अपनी बात कह सकेंगी। यही नहीं महिला हेल्प डेस्क या सीक्रेट रूम में दिखने वाली किसी जगह पर वह सारे नंबर (1090, 181, 112,1076,1098, और 102) लिखें रहेंगे जिन पर कोई महिला जरूरत पर मदद के लिए कॉल कर सके। नंबरों के साथ इनका दुरुपयोग करने वालों के लिए चेतावनी भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।



एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के सभी 1,535 थानों पर स्थापित होने वाले महिला हेल्प डेस्क की डिजिटल शुरुआत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने

24 घंटे में कोरोना के 54366 नए मामले सामने आए, 690 लोगों की हुई मौत

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली। भारत में कोविड-19 के दैनिक नए मामले लगातार पांचवें दिन 60000 से नीचे रहे। 24 घंटे के अंतराल में 54366 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामले शुक्रवार को बढ़कर 7761312 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कुल 54366 नए मामले सामने आए जबकि 690 और मौतें होने से देश में इस महामारी में मरने वालों की संख्या 117306 हो गई। देश में कुल 6948497 लोगों ने अब तक इस बीमारी से निजात पाई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर अब 89153 प्रतिशत तक हो गई है जबकि मृत्यु दर 1151 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाखए 23 अगस्त को 30 लाखए 5 सितंबर को 40 लाखए 16 सितंबर को 50 लाखए 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख के पार हो गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ;आईसीएमआर के अनुसारए बृहस्पतिवार को 1442722 नमूनों की जांच होने के साथ 23 अक्टूबर तक कुल 100113085 नमूनों की जांच हो चुकी है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब, सांस लेना मुश्किल

(विशेष संवाददाता) नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में और अधिक गिरावट के बाद कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सरकारी एजेंसियों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि आगामी दो दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब होगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खराब श्रेणी में है जो शुक्रवार सुबह 374 और शाम के समय 366 दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 302 था। पृथ्वी विज्ञान की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में है। उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एक्जआई को अछ, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब तथा 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से विकसित विवेक विहार में 422, रोहिणी में 401, जहंगीरपुरी में 418 और पटपटवांज में 405 दर्ज किया गया। सफर के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में हवा है। सफर ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है और बृहस्पतिवार को इनकी संख्या 1,213 थी। हवा की गति अभी प्रदूषक तत्वों को दिल्ली की तरफ धकेलने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। आज पराली से दिल्ली में पीएम 2.5 का योगदान 17 फीसदी दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि वायु की गुणवत्ता में और गिरावट दर्ज हो सकती है। क्योंकि पीएम 10 और पीएम 2.5 कणों की संख्या हवा में बढ़ रही है। पीएम 10 का व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है और पीएम 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म प्रदूषक कण होते हैं। आईएमडी के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद शर्मा ने पीटीआईभाषा से बृहस्पतिवार को कहा, वायु गुणवत्ता आगामी दो दिनों में यानी 24 अक्टूबर तक और खराब होगी। पराली जलाने के अलावा अन्य कारक भी हैं, जिससे वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। इनमें वाहन प्रदूषण और अपशिष्टों को जलाना भी शामिल है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है जिसके लिए इसने दिल्ली में 100 ट्रैफिक सिग्नलों पर 2,500 पर्यावरण मार्शल तैनात किए हैं। इस अभियान को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 26 अक्टूबर से क्रियान्वित किया जाएगा जो 15 नवंबर तक चलेगा। अभियान की अवधि सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक की होगी। सरकार ने कहा है कि यह एक जागरूकता कार्यक्रम है और इसके लिए किसी तरह का चालान नहीं काटा जाएगा।



समीर/एप के अनुसार दिल्ली में 10 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। अलीपुर में यह सूचकांक 447, शादीपुर में 441, मुंडका में 419, वजीरपुर में 432, आनंद विहार में 405, बवाना में 413,

FATF का बड़ा फैसला, ग्रे लिस्ट ही बना रहेगा पाक, आतंकी सरगनाओं पर करनी ही होगी कार्रवाई

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली। पाकिस्तान एफएटीएफ के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अगर उसे फाइनेंसिएल महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देना होगा। एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से बाहर निकलना है तो भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी जैसे दाउद इब्राहिम, जकीरउररहमान हाफिज साईद और इनके सहयोगियों के समूचे अर्थ तंत्र को खत्म करना होगा और इसके सबूत अंतरराष्ट्रीय विरादरी के सामने रखने होंगे। आतंकी फंडिंग रोकने व गैर कानूनी तरीके से नकदी हस्तांतरण पर रोक लगाने की पुख्ता व्यवस्था करे। एफएटीएफ ने पाक सरकार को 27 कार्य सौंपे थे। पाकिस्तान सरकार ने इनमें से 21 कार्य पूरे कर इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी है। एफएटीएफ ने इसके लिए पाक सरकार की तारीफ भी की है। लेकिन शेष बचे छह कार्य ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला कार्य यह है कि पाकिस्तान सरकार को एजेंटियाँ आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे। आतंकी संगठनों व आतंकीयों के खिलाफ तमाम मामलों की जांच करे। दूसरा कार्य है आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच के बाद प्रभावशाली तरीके से प्रतिबंध लगाये जाएं। तीसरा कार्य है पाकिस्तान सरकार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 1267 व 1373 प्रावधानों के तहत घोषित आतंकीयों व इनकी तरह से काम करने वाले आतंकीयों के खिलाफ संपूर्ण तरीके से वित्तीय प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करे।



इन छह कार्यों में यह भी शामिल है कि पाकिस्तान हर तरह की आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने की पुख्ता व्यवस्था करे। एफएटीएफ ने पाक सरकार को 27 कार्य सौंपे थे। पाकिस्तान सरकार ने इनमें से 21 कार्य पूरे कर इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी है। एफएटीएफ ने इसके लिए पाक सरकार की तारीफ भी की है। लेकिन शेष बचे छह कार्य ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला कार्य यह है कि पाकिस्तान सरकार को एजेंटियाँ आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे। आतंकी संगठनों व आतंकीयों के खिलाफ तमाम मामलों की जांच करे। दूसरा कार्य है आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच के बाद प्रभावशाली तरीके से प्रतिबंध लगाये जाएं। तीसरा कार्य है पाकिस्तान सरकार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 1267 व 1373 प्रावधानों के तहत घोषित आतंकीयों व इनकी तरह से काम करने वाले आतंकीयों के खिलाफ संपूर्ण तरीके से वित्तीय प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करे।

एक नजर

फेल्टा पेपर रिट्रैप जांच के लिए आईसीएमआर ने जारी किये परामर्श नवी दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने देश में निर्मित फेल्टा पेपर रिट्रैप जांच पर परामर्श जारी की है, यह सार्वसीओवी2 पहचान के लिए सीआरआई एसीआरसीएमआर 2 तकनीक आधारित है। इस जांच में सीआरआई एसपीआर जीन इंजीनियरिंग से जुड़ी आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है जो सार्वसीओवी2 के जीन से जुड़े तत्व की पहचान एक घंटे के भीतर कर लेता है। आईसीएमआर की ओर से जारी परामर्श में बताया गया है कि इसके उत्पादकों का दावा है कि इस जांच में आम व्यक्ति के संक्रमित या संक्रमित नहीं होने की पुष्टि होती है तो उसके बाद आरटीपीसीआर जांच की जरूरत नहीं है। इसे 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (सीएसआईआर) के 'जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान' (आईजीआईबी), दिल्ली ने तैयार किया है। इसका सत्यापन नेशनल सेंटर फॉर बायोलोजिकल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया है। इस जांच को देश में करने की अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने दी है। आईसीएमआर ने एक बयान में बताया कि इस जांच में सार्वसीओवी2 वायरस की पहचान की जाती है।

उत्कर कर् के कोरेना का मुकाबला: अभिनव सहाय नई दिल्ली। राजीव गांधी स्थित राजधानी कॉलेज की रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री सोसायटी व एनएसएस ने मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अंतर्गत पावर टू यूथ: बैलिस्टिक वेलेस प्रोग्राम चलाया गया। इस वेबिनार के माध्यम से कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों को वेलेनेस के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता राजधानी कॉलेज के पूर्व छात्र अभिनव सहाय ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्रों को बताया कि अपनी अंदरूनी शक्तियों का किस तरह से आभास होना चाहिए तथा युवाओं को अपनी शक्तियों का प्रयोग समाज के समग्र कल्याण हेतु कैसे करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य को अपनी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित करनी चाहिए। संतुलित आहार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि इस कोरोना महामारी के चलते हम युवाओं को अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, बल्कि दिन प्रतिदिन एक वीर योद्धा बनकर इस महामारी का डटकर सामना करना है। कार्यक्रम का संचालन सोसायटी की संयोजक डॉ शर्मिला यादव द्वारा किया गया। इस वेबिनार में राजधानी कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजेश गिरि भी उपस्थित रहे। कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्रों में बड़ी संख्या में एकजुट होकर भाग लिया। वेबिनार से जुड़े छात्रों के मन में आए हुए प्रश्नों के उत्तर अभिनव सहाय एवं उनके सहायक अजय त्यागी ने मिलकर बड़े ही सहज एवं सरल शब्दों में दिए।

LNJP अस्पताल में 1500 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशियलिटी ब्लॉक बनेगा

अत्याधुनिक डिजाइन और आधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा

(विशेष संवाददाता) नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एलएनजेपी अस्पताल में 1500 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी ब्लॉक की आज आधारशिला रखी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोहई साल के अंदर 1500 बेड जुड़ने के बाद एलएनजेपी 3800 बेड का हो जाएगा, जो अत्याधुनिक डिजाइन और आधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी सुविधाओं से युक्त 1500 बेड बनाने

में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। हम अपने सभी प्रोजेक्ट समय से पूरा करने के साथ ही पैसे भी बचा रहे हैं, जबकि अन्य राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट पूरे होने में 1010 साल लग जाते हैं और 200 करोड़ का बजट है, तो बड़ कर हजार करोड़ का हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान वाहन प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने दिल्ली के सभी लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री सतिश जैन ने कहा कि सीएम का सपना दिल्ली को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने का है और एलएनजेपी अस्पताल का इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पूरी तरह से वातानुकूलित मेडिकल ब्लॉक की बेड के मेडिकल ब्लॉक की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री

ब्लॉक में 1500 बेड जोड़े जा रहे हैं। अभी एलएनजेपी अस्पताल में 2000 पहले से ही बेड हैं। यह 1500 जोड़े जाने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में 3500 बेड हो जाएगी। बताया गया है कि अस्पताल के एक अन्य ब्लॉक में भी 300 बेड और बनाए जा रहे हैं। इस तरह, अगले दो से दूई साल के अंदर एलएनजेपी अस्पताल 3800 बेड का अस्पताल हो जाएगा, जो पूरे देश के अंदर सबसे बड़े अस्पतालों में से एक होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल काफी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उस पूरे एरिया के अंदर कुल 2000 बेड हैं, जबकि अस्पताल के अंदर खाली एक छोटी सी जगह के अंदर 25 मॉडल बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 1500 बेड होंगे। एक तरह से इसमें आर्किटेक्ट ने भी काफी अच्छे काम किया है और इसकी आधुनिक डिजाइन है, जिससे कि बाद में भी कोई बदलाव किया जा सकता है और नई सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। इस अस्पताल में मेडिकल सुविधाएं भी सबसे आधुनिक होंगी। मुझे खुशी है कि दिल्ली के रहने वाले लोग देश की राजधानी में रहते हैं, तो देश की राजधानी में रहते हुए उन्हें विश्वस्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होना चाहिए।

एक माह में 4 जमानत याचिकाएं दाखिल करने पर जुर्माना

नई दिल्ली। एक महीने में चार बार जमानत याचिकाएं दाखिल करने वाले आरोपी पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने के कारण आरोपी को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में जुर्माने की रकम जमा करानी होगी। द्वारा स्थित अतिरिक्त सत्र न्याधीश गोमती मनोचा की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगली बार तब तक आरोपी की जमानत याचिका को सुनने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी तरफ से जुर्माना रकम जमा कराने की रसीद अदालत के समक्ष पेश नहीं कर दी जाएगी। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात बकली या आरोपी को समझ में क्यों नहीं आती कि यह मुश्किल समय है। रोटेशन में अदालत में सुनवाई चल रही है। ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बावजूद एक ही मुद्दे को अदालत लेकर पहुंचने वाले लोगों की वजह से अन्य मामलों प्रभावित होते हैं। अगर चार दिन पहले जमानत याचिका खारिज हुई है।

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म लक्ष्मी बम के विरोध में प्रदर्शन

(वूमैन एक्सप्रेस ब्यूरो) नई दिल्ली। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एवं लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्म के विरोध में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने आज जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करके फिल्म पर प्रतिबंध लगाने अपने आदेश में कहा है कि अगली बार तब तक आरोपी की जमानत याचिका को सुनने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी तरफ से जुर्माना रकम जमा कराने की रसीद अदालत के समक्ष पेश नहीं कर दी जाएगी। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात बकली या आरोपी को समझ में क्यों नहीं आती कि यह मुश्किल समय है। रोटेशन में अदालत में सुनवाई चल रही है। ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बावजूद एक ही मुद्दे को अदालत लेकर पहुंचने वाले लोगों की वजह से अन्य मामलों प्रभावित होते हैं। अगर चार दिन पहले जमानत याचिका खारिज हुई है।

फिल्मों को अपने यहां प्रदर्शित करने की अनुमति देनी चाहिए। गोयल ने कहा कि फिल्म की निर्माता शबाना खान विगत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय रही है। कश्मीर और धारा सिनेमा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रोक दिया था। हमारे घोर विरोध के दृष्टिगत फिल्म पूरे देश में संशोधित करने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने वर्तमान फिल्म निर्माता समाज और फिल्मों को अपने यहां प्रदर्शित करने की अनुमति देनी चाहिए। गोयल ने कहा कि फिल्म की निर्माता शबाना खान विगत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय रही है। कश्मीर और धारा सिनेमा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रोक दिया था। हमारे घोर विरोध के दृष्टिगत फिल्म पूरे देश में संशोधित करने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने वर्तमान फिल्म निर्माता समाज और फिल्मों को अपने यहां प्रदर्शित करने की अनुमति देनी चाहिए। गोयल ने कहा कि फिल्म की निर्माता शबाना खान विगत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय रही है। कश्मीर और धारा सिनेमा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रोक दिया था। हमारे घोर विरोध के दृष्टिगत फिल्म पूरे देश में संशोधित करने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने वर्तमान फिल्म निर्माता समाज और फिल्मों को अपने यहां प्रदर्शित करने की अनुमति देनी चाहिए। गोयल ने कहा कि फिल्म की निर्माता शबाना खान विगत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय रही है। कश्मीर और धारा सिनेमा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रोक दिया था। हमारे घोर विरोध के दृष्टिगत फिल्म पूरे देश में संशोधित करने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने वर्तमान फिल्म निर्माता समाज और

एलओसी पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड 'स्मार्ट' बाड़

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (वेबवार्ता।) पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में काफी सुधार किया है। सीमा पर मौजूदा बाड़ को कई सेंसर के साथ एकीकृत करके हाइब्रिड 'स्मार्ट' बाड़ लगाई जा रही है। इस हाइटेक बाड़ को लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और अन्य कैमरों के साथ जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि स्मार्ट बाड़ के नए हाइब्रिड मॉडल की लागत लगभग 10 लाख रुपये प्रति किमी होगी और इस वर्ष सीमा पर 60 किमी. हाइटेक बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जायेगा। चूंकि इस सेंसरयुक्त हाइब्रिड मॉडल की बाड़ की लागत ज्यादा है, इसलिए 700 किमी. की पूरी एलओसी पर इसके लगाने का अभी फैसला नहीं किया गया है। पहले 2.4 किमी एरिया में हाइटेक बाड़ के लिए

लगभग 10 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था। हाल के महीनों में सेना ने नियंत्रण रेखा के करीब सैनिकों को कमकम दूरी पर तैनात किया है, जिससे इस साल घुसपैठ में गिरावट आई है। इस बार अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 30 आतंकियों ने घुसपैठ की है जबकि पिछले साल इस समय तक 130 आतंकियों में गिरावट आई है। सूत्रों का कहना है कि एलओसी पर एंटीइंफिल्ट्रेशन गिड को कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। निगरानी के लिए सैनिकों को बड़े और छोटे दोनों तरह के ड्रोन दिए गए हैं। लगभग 700 किमी. की सीमा पर लगी मौजूदा बाड़ को एंटीइंफिल्ट्रेशन ऑक्सट्रेल सिस्टम कहा जाता है। कंसर्टिना तार से बनी दोहरी पंक्ति वाली यह बाड़ 2003 और 2005 के बीच लगाई गई थी। इन 1517 साल के बीच बर्फानी के कारण हर साल इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती थी।

रेलवे अब घर से ट्रेन और ट्रेन से घर तक पहुंचाएगी आपका सामान

(वूमैन एक्सप्रेस ब्यूरो) नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि रेलवे नए उपायों से राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली मंडल ने हाल ही में गैर क्रियायारजस्व अर्जन योजना के अंतर्गत एप आधारित बेस ऑन व्हील्स सेवा के लिए टेका प्रदान करके मील का पत्थर स्थापित किया है। देश में रेलयात्रियों के लिए यह अगले चरण की पहली सेवा होगी। बीओडब्ल्यू एप के द्वारा रेलयात्री अपने सामान को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक लाने अथवा रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन करेंगे। यात्री का सामान सुरक्षित तरीके से लेकर रेलयात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार उसके कोच या घर तक पहुंचाने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। नाम मात्र के शुल्क पर रेलयात्रियों को सामान की डोरटूडोर सेवा फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और यात्री के घर से उसका सामान रेलगाड़ी में उसके कोच तक अथवा उसके कोच से उसके घर तक सुरामता से पहुंचाया जाएगा। यह सेवा रेलयात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इस सेवा को खास खूबी यह है कि सामान की सुपुर्दगी रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित की जाएगी। इसके फलस्वरूप यात्री कोच तक सामान लाने या ले जाने की परेशानी से मुक्त हो एक अलग ही प्रकार की यात्रा का अनुभव करेंगे। शुरूआत में यह सेवा नई दिल्ली, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिला, गाजियाबाद और गुडगांव रेलवे स्टेशनों से चढ़ने वाले रेलयात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इस सेवा से न केवल यात्री लाभान्वित होंगे।

निगम की बकाया राशि तुरन्त दें दिल्ली सरकार: विजेन्द्र यादव

(वूमैन एक्सप्रेस ब्यूरो) नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने कहा कि निगम अपने दायित्व को ठीक से निभा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 1024 करोड़ रुपये बकाया राशि दे। जिससे कि निगम को ठीक से चलाया जा सके। निगम में कार्यत कर्मचारियों का वेतन समय से दिया जा सके। यादव ने कहा डंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर निगम का स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर हर वर्ष कार्य करता है, लेकिन 10 मिनट कार्य करके इसका श्रेय दिल्ली सरकार लेना चाहती है। स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने आगे कहा कि जो दिल्ली के सीएम विज्ञापन पर खर्च करके दिल्ली की जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे है अगर यही पैसा दिल्ली के विकास कार्यों में लगाया जाये तो दिल्ली की जनता को कई समस्याओं से राहत मिल सकती है इस लिए मेरी दिल्ली सरकार से अपील है कि विज्ञापन पर कम खर्च करके दिल्ली के विकास पर अधिक से अधिक खर्च किया जाये।

आरबीआई ने की घोषणा, अब क्रिक रिसॉन्स क्यूआर कोड को जारी करेंगी पेमेंट कंपनियां

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (वेबवार्ता।) भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को नया स्व अधिकार वाला क्यूआर कोड जारी करने से मना कर दिया है। डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए आरबीआई यह फैसला लिया है। आरबीआई का कहना है कि स्मार्टफोन्स इस समय देशव्यापी हो गए हैं और इंपेमेंट्स का आधार क्यूआर बनते जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को 31 मार्च 2022 तक अंतरसंचालित क्रिक रिसॉन्स क्यूआर कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट ऑपरेटर्स को एक ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा, जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है। प्रोसेस दीपक फाटक की अगुवाई वाली एक कमेटी ने अगले दो साल में अंतरसंचालित क्यूआर कोड्स में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए थे। वर्तमान में, देश में तीन तरह के क्यूआर कोड चलते हैं। ये भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोपराइटी क्यूआर कोड हैं। आरबीआई के इस आदेश के अनुसार, देश में डिजिटल और सुरक्षित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है। जिसके अनुसार पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा, जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है। यूपीआई और भारत पहले की तरह ही जारी रहेंगे। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को पहली करनी होगी। फाटक कमेटी के इस सुझाव से पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से आम लोगों को सहूलियत होगी और पेमेंट सिस्टम भी पहले से बेहतर हो सकेगा।

BUSINET

ALOMED

एलमण्डॉल

तारुन्ती ऑफ हेल्थ
तारुन्ती ऑफ ब्यूटी

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIC's PREMIUM POINT
Authorized Premium Collection Centre

GET ALL FINANCIAL SERVICES UNDER ONE ROOF

हो सकता है कि बीमा दुर्घटना न खरीद सकें...
किन्तु बीमा का न होना दुर्घटना बट कर सकता है।

K.K. PANDEY
INSURANCE PROFESSIONAL

Ph. 0120-2820066

ADD. MG TOWER, D-1/B-4, RDC RAJNAGAR (OPP. TELEPHONE EXCHANGE), GHAZIABAD

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदी का सबसे बड़ा कृषि सुधार कानून देश में लाए



प्रश्न: मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है, विपक्षी विरोध कर रहे हैं ?
उत्तर : नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किसानों के लिए फसल किया है, वो केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए एक सार्थक कदम है। ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा किसान सुधार रिफॉर्म है, जिससे किसान व किसानों खुशहाल होंगे, किसान अपने जीवन को खुद सुधार

सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में किसानों की मिट्टी से लेकर, किसानों की मिट्टी की जांच, किसानों की मिट्टी को क्या चाहिए उसकी योजनाएँ लगभग 11 करोड़ खेतों की मिट्टी की जांच की गई है। फसल बेचने की चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए, बुआई से पहले फसल के उचित दाम तय करना, जैसे महत्वपूर्ण कदम पिछले कुछ दिनों में उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से आज किसान आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए इजराइल की किसानों के

बराबर भारत की किसानों को खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने 9 अगस्त, 2017 को संसद के सदन में यह संकल्प लिया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाएगा। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दिन रात प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं।
प्रश्न : विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा?

उत्तर : आपने एमएसपी की बात की है, एमएसपी को ऑटोमेटिक मोड पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में पंजाब की धरती पर खड़े होकर शुरू किया था और स्वामीनाथन रिपोर्ट को किसानों के हित में लागू करने का नीतिगत फैसला लिया था। सरकार ने पहले ही कह दिया कि एमएसपी है और आगे भी जारी रहेगा।

प्रश्न: कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि भाजपा किसान विरोधी है। नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं?

उत्तर : राहुल गांधी जी पार्ट टाइम राजनेता हैं, जिनके लिए सेवा नहीं अपितु साधनों का उपभोग एमएसपी आराम विद सेवन स्टार लाईफ स्टाइल महत्वपूर्ण है। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस शासनकाल में जब उनकी माताजी सोनिया गांधी देश की सरकार को कठपुतली की तरह चलाती थीं, तब 2009 और 2010 का कृषि मंत्रालय का कुल बजट 12 हजार करोड़ रुपए होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आज कृषि मंत्रालय का बजट 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपए का है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की किसानों के प्रति वचनबद्धता है और उनके किए हुए कार्य आज बोल रहे हैं। जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, वो ऐसी छेटी, ओछी

राहुल गांधी पार्ट टाइम राजनेता हैं, उनके लिए सेवा नहीं, ऐसे आराम महत्वपूर्ण है

- पंजाब में भाजपा की पहली सरकार फरवरी 2022 में बनेगी।
- भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, बाकी पार्टियां पीछे।
- किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक कदम।
- अकाली दल के पास कई किसान नेता थे, लेकिन मंत्री हरसिमरत कौर को बनवाया।

ही नहीं हुआ था।
प्रश्न : स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ना लागू करने का आरोप लगा रहा है या उसे लागू करने की मांग हो रही है ?

उत्तर : मेरे कांग्रेस के मित्र कैप्टन अमरेंद्र सिंह व सो कॉल्ड कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी जी झूठ, फरेब और षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक सत्ता में रही, इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अपने पांव के नीचे दबा कर रखा। हमारी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने 2018 को पंजाब के मलौट में खड़े होकर किसानों के मध्य घोषणा की थी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मानने का नीतिगत फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब खरीद ऑटोमेटिक मोड पर होगी और एमएसपी

सरकार के निर्णयों के बारे में नहीं बताती तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, यह एक पति और पत्नी के मध्य का विषय है।

प्रश्न : अकाली दल आरोप लगा रहा है भाजपा किसान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है?

उत्तर : मैं सुखबीर सिंह जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 26 मई, 2014 को जब मोदी सरकार बनी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाली दल से सरकार में मंत्री बनाने के लिए एक प्रतिनिधि मांगा था। उस समय सदन में किसान नेता सरदार सुखदेव सिंह ढींसा, किसान नेता बलविंदर सिंह भुट्टा, किसान नेता जयदेव प्रेम सिंह चंदमाजरा व किसान नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा भी सांसद थे, पर तत्कालीन किसानों की सबसे बड़ी पार्टी के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसी किसान नेता को प्रतिनिधि भेजने की बजाए कॉरपोरेट घराने की बेटी श्रीमती हरसिमरत

पंजाब के लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करेगी।
प्रश्न : क्या नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में शामिल हो रहे हैं?

उत्तर : भाजपा में बहुत लोग शामिल होना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी के मुखिया के दायें बायें वाले भी और मुंगेरि लाल के हसीन सपने देखने वाले नेताओं के दायें बायें वाले भी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। समय आने दीजिए उनके नाम के खुलासे भी करेंगे और उनको शामिल करके पंजाब की राजनीति को एक नई दिशा भी देंगे। भाजपा की नीति और नियत एक है सबका साथ, सबका विकास। बाकी रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की तो आप उनसे ही पुछिए उनकी योजना क्या है। उनकी श्रीमती हर 15 दिन बाद एक बयान जारी कर देती है कि वह भाजपा में जाना चाहती है। बाकी कांग्रेस में तो उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनने की शहनाईयां बज रही हैं, आप उनके कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं।

प्रश्न : सिक्खों की सर्वोच्च संस्था एसजीपीसी में 2016 से चुनाव टल रहा था, अचानक बादल दल के अलग होते ही केंद्र सरकार एक्टिव हो गई। क्या भाजपा धार्मिक सिवासत में दखल देगी?

उत्तर : ये बात ठीक है कि पिछले 10 वर्षों से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों के साथ कोई लेना देना नहीं है। न भाजपा गुरुद्वारा के प्रबंधन का चुनाव लड़ती है, ना ही किसी को सपोर्ट करती है। ये पूरी तरह से गुरुद्वारा के प्रबंध एवं उनकी कमेटी के चुनाव हैं। भाजपा शामिल नहीं होगी।

पंजाब के अमृतसर से उत्तरक चंडीगढ़ होते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भाजपा के कद्दावर नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों एवं इस बीच हुए विधानसभा चुनावों में वह पदों के पीछे रहते हुए संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का वॉर रूम भी बड़ी कुशलता से संभाला और अच्छे नतीजे पार्टी को मिले। उनसे दुनिया के पहले महिलाओं के एकमात्र दैनिक समाचार पत्र वूमैन एक्सप्रेस की चीफ एडिटर खुशबू पाण्डेय ने खास बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश...



विशेष साक्षात्कार वूमैन एक्सप्रेस
“ मोदी सरकार ने किसानों की क्रयविक्रय एवं मोलभाव की शक्ति को बढ़ाने के लिए 10 हजार नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। ”
तरुण चुग
राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा

का रेट ऑटोमेटिक मोड पर होगा। राहुल गांधी जी आपको जवाब देना होगा कि आपने 10 साल तक व उससे पीछे भी लगभग 40 साल के शासन में किसानों व किसानों की चिंता क्यों नहीं की।

प्रश्न : राहुल गांधी ने पंजाब दौरे में कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो किसान बिलों को फाड़ देंगे?

उत्तर : राहुल गांधी जी पंजाब के अंदर केवल सैर सपाटे के लिए गए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी ही सरकारएँ उनकी ही पार्टी ने 9 जनवरी, 2017 को पंजाब का घोषण पत्र जारी किया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे और उसमें कांग्रेस ने 90 हजार करोड़ रुपए किसानों कर्ज को माफ करने की तथा प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की थी। अब कांग्रेस की सरकार को आए 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो वादा वफा नहीं हुआ है, पर 400 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

आप अगर पंजाब में सचमुच किसानों के लिए कुछ करने आए थे, तो उन आत्महत्या किए हुए किसानों की विधवाओं के घरों का दरवाजा तो खटखटाया होता। पर बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के पास उनकी सरकार की वादा. खिलाफी के कारण आत्महत्या किए 400 से ज्यादा किसानों को सुनने के लिए समय नहीं है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले नकली, जहरीली कांग्रेस द्वारा स्थापित माफिया द्वारा बेची गई शराब के कारण मारे गए 124 के करीब दलित भाईयों की मौत पर राहुल गांधी ने एक टिवट तक नहीं किया था। यह राहुल गांधी और कैप्टन अमरेंद्र सिंह का दोहरा चेहरा दर्शाता है।

प्रश्न : शिरोमणि अकाली दल शुरू से इस बिल का समर्थन करता रहा है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अचानक संसद में विरोध करने लगे, ऐसा क्यों?

उत्तर : दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमारे साथ बैठकर किसान रिफॉर्म का इतना बड़ा बिल कैबिनेट में पास किया, आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। सुखबीर सिंह कह रहे हैं कि मुझे पिछले 6 वर्षों में सरकार के क्या निर्णय हुए, उसकी जानकारी नहीं है, हम से पूछ नहीं गया। सुखबीर सिंह जी 26 मई, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार का हर निर्णय कैबिनेट में हुआ है और हर कैबिनेट में आपको पत्नी हरसिमरत कौर बादल उपस्थित रही हैं। अब अगर आपको आपको

कौर बादल मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भेजा। बाद में वह केंद्रीय मंत्री बनीं। यह तो देश और उनकी पार्टी खुद देख रही है कि कौन किसान विरोधी है।

प्रश्न : पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग लड़ेंगी या गठजोड़ होगा ?

उत्तर : भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। किसानों, गरीबों, वंचितों की पार्टी है। भाजपा ने 1992 तक अकेले चुनाव लड़ा था और 1992 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 64 को सीटें लड़ने पर 16.08 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। अब हम 117 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। ये वोट प्रतिशत लगभग 30 प्रतिशत बनता है। अब हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा विश्व स्तरीय निर्णय लेने वाला, गरीबों, वंचितों व किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला नेता है। निश्चित रूप से भाजपा 117 सीटें लड़ेगी। साथ ही पंजाब, पंजाबीयत और पंजाबी भाईचारे की रक्षा करने वाला, वंचितों, गरीबों, किसानों व युवाओं के लिए काम करने वाली, महाराज रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था को आदर्श मानकर चलने वाली, पंजाबी की भाजपा की पहली सरकार फरवरी 2022 में बनेगी जा रही है।

प्रश्न : पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला किस पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस, आप या अकाली दल के साथ ?

उत्तर : 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के मध्य मुकाबला होगा, बाकी सब पार्टियां पिछड़ चुकी हैं। 3.4 नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं। जनता बदलाव चाहती है। भाजपा शासन व्यवस्था में बदलाव, गरीब, वंचित और किसानों को मध्य में रखकर योजनाएं बनाएंगी, जिसके अंदर पंजाब के सभी उपभोक्ता को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और नशों के हैंडलर को नहीं, हम नशों के किंगप्रिंस को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अमन, शान व कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

प्रश्न : पंजाब में चर्चा है कि अकाली दल से बागी होकर नई पार्टी बनाने वालों से भाजपा गठबंधन कर सकती है?

उत्तर : 2017 में जिस अकाली दल के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा था, उसमें से दो अकाली दल पहले ही निकल चुके हैं। इसमें से एक है सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की पार्टी और दूसरा सरदार सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी। भाजपा अपने बल पर, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएगी, जो

प्रश्न पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के बिलों को अपनी विधानसभा में रोकेगी?

उत्तर : किसानों से प्रतिवर्ष लगभग 35 सौ करोड़ रुपए टैक्स में रूप में उगाने वाले कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी अगर इस सदी का सबसे बड़ा वादा खिलाफी का अवार्ड होगा तो, वो उनको मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने मैनफेस्टो में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, सरकार बनते ही वह मुकर गए। अब जब केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिलों में कुछ बदलाव कर दिया तो इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार एवं खुद कैप्टन चाहते ही नहीं हैं कि गरीब किसानों का भला हो, यही कारण है कि वह विरोध करता रहे हैं।

प्रश्न राहुल गांधी ने सिक्खों के साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही थी, कितनी सच्चाई है ?

उत्तर : राहुल गांधी जीए पंजाब की वंश ने 1984 के सिख कत्लोमार को संरक्षण दिया, संचालित किया, इसमें शामिल कातिल नेताओं को महामामंडित किया, पालाए पोशाए संरक्षण दिया, श्री हरिमंदिर साहिब पर टैंक चढ़ा दिए, उनके मुख से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। उनके मुंह से इतना बड़ा झूठ अच्छा नहीं लगता। 1984 के सिख कत्लोमार की एफआईआर की फाइलें 30 वर्षों तक टू.कोर्ट नहीं हो पाईं।

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी बनाईं। जिसकी बदौलत आज सज्जन कुमार जेल में हैं, लेकिन आज भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 1984 सिख दंगों पर बड़बोले बयान देने वाले, जगदीश टाइटलर भी आज कांग्रेस के नेता के रूप में शोभनीय हैं। जिस व्यक्ति पर गुरुद्वारा को जलाने के बारे में, चरमदीय गवाह द्वारा अदालत में बयान दिया हो, उस कमलनाथ को सुशोभित व महामामंडित करके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो भी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या राहुल गांधी जी ये सच नहीं है कि जिन्होंने सिक्खों के गलों में टायर डाले, उनको जिंदा जलाया, गुरुद्वारे जला दिए, चुन चुन कर सिक्खों की दुकानें लुटी गईं, जलाई गईं, सिक्खों के शिक्षण संस्थान जला दिए गए। ऐसे लोगों को कांग्रेस 30 वर्ष तक अपने आंचल में छिपा कर पालती रही, महामामंडित करती रही, पद प्रतिष्ठ करती रही।



राजनीति कर देश का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता उनका असली सच जानती है।

प्रश्न : मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं?

उत्तर : मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पिता राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में भाषण में कहा था कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूँ और किसानों के पास 14 रुपए पहुंचते हैं। ये उनके समय में भ्रष्टाचार की हालत थी, जबकि आज 192 हजार करोड़ रुपए सीधे किसान के डीबीटी के माध्यम से पहुंच चुके हैं।

प्रश्न : किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की क्या योजना है?

उत्तर : मोदी सरकार ने किसानों के समूह को बढ़ाने के लिए किसानों की क्रयविक्रय शक्ति एवं बारोनिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए 10 हजार नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए 1850 करोड़ रुपए का सपोर्ट उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से देने की योजना बनाई है। किसान समूह हो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए का पैकेज, किसान खुशहाल हो उसके लिए, फार्मर इम्प्रोस्ट्रक्चर के लिए, किसान आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए, एक लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। फिशरी के लिए 20 हजार करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 15 हजार करोड़ रुपए, हरबल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में इन मदों में कोई काम